all the cases. It has also implemented the suggestions made to prevent irregularities in assessments. Other measures taken by the Department on its own are strentghening the inspection and vigilance set up. A net work of preventive vigilance has also been already laid.

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

2126. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की अलग-अलग कितनी बैठकें हुई और वर्ष में चार से अधिक बैठकें न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और उनके द्वारा कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है और वे कितनी मिसिलों में अपना कार्य हिन्दी में करते हैं, समिति में कौन-कौन से गैर-सरकारी सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में है और उन्होंने कितनी बैठकों में भाग लिया ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये वार्षिक कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1985, 1986 और 1987 के दौरान गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की क्रमशः एक तीन और एक बैठकें हुई । इस समिति को जून, 1985 में पुनर्गठित किया गया था इसलिए इस वर्ष के दौरान अक्तूबर, के महीने में इसकी केवल एक बार बैठक हो सकी । वर्ष 1986 और 1987 के दौरान कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठक नहीं की जा सकी ।

(ख) चूंकि मंत्रालय को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके नामों के नहीं बल्कि पदनामों के आधार पर नियुक्त किया जाता है इसलिए नाम समय-समय पर बदलते रहते हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव उप-निदेशक (रा. भा.) हैं जो अपना सभी कार्य हिन्दी में कर रहे हैं । समिति के अध्यक्ष और अधिकांश अन्य सदस्य भी अपना 15–25% कार्य हिन्दी में कर रहे हैं जिसमें कुछ फाइलों पर लिखी हुई उनकी टिप्पणियां भी शामिल है । विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. मलिक मोहम्मद को राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है लेकिन बैठकों के समय बाहर दौरों पर होने के कारण वे समिति की किसी बैठक में उपस्थित नही हो सके ।

(ग) राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय में प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है । मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाता है और इसका प्रबोधन किया जाता है ।

2127. [*Transferred to the 24th March*, 1988]

परम्परागत मदों के निर्यातकों में वृद्धि

2128. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परम्परागत मदों जैसे चाय, जूट, रेशम और आधुनिक इलैक्ट्रानिकी सामान के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) निर्यात में इस वृद्धि में व्यापार मेलों का कितना योगदान है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मेले आयोजित करने पर कितनी राशि खर्च की गयी ; और

(ग) इन मेलों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1984-85, 1985-86, 1986-87 के दौरान परम्परागत मदों का निर्यात पिछले वर्ष की उन्हीं अवधियों की तुलना में क्रमशः 40.1 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत, तथा 3.3 प्रतिशत बढ़ गया । आधुनिक इलैक्ट्रानिक माल के निर्यात संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है और जैसे ही उन्हें एकत्र कर लिया जायेगा, सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) विभिन्न व्यापार मेलों के फलस्वरूप निर्यातों में होने वाली वृद्धि की मात्रा बताना संभव नहीं है, क्योंकि परिणाम मेले के बाद महीनों और कभी-कभी वर्षों में प्राप्त होते हैं । 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय क्रमशः 10.71 करोड़ रु०, 6.22 करोड़ रु० तथा 8.41 करोड़ रु० रहा ।

(ग) भारत में आयोजित मेलों में प्रचार अभियानों तथा प्रदर्शनों में हिन्दी का व्यापक उपयोग किया जाता है । विदेशी मिलों में, विशेषरूप से जहां हिन्दी जानने वाले आगन्तुकों को लक्षित किया जाता है, जहां कहीं सम्भव होता है, इसका उपयोग किया जाता है ।

.Margin Money Assistance Scheme.

2129. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Wasteland Development Board has formulated a Central Sector Scheme known as the Margin Money Assistance Scheme with a view to improving the viabilities of the projects on wastelands; and

(b) if so, what are the main objectives of the Scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORCES (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes Sir.

(b) The main objectives of the Scheme are to promote plantation on wastelands of fuelwood, fodder, small timber and commercial timber species by Government Corporations Municipalities, Urban Development Authorities and other autonomous or semi-government bodies by providing the margin money needed to attract funds from banks and financial institutions for such projects.

Border dispute between Arunachal Pradesh and Assam

2130. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the reaction of the Central Government to the long standing border dispute between Arunachal Pradesh and Assam; and

(b) whether Government are aware that people belonging to Nishi tribe of Arunachal Pradesh are securing arms and getting arms training from across the border?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) There is a boundary problem involving Assam and Arunachal Pradesh relating to demarcation of the Constitutional boundary on the ground. A tripartite committee consisting of the representatives of Governments of Assam, Arunachal Pradesh and Survey of India, is already in existence to resolve the Assam-Arunachal Pradesh boundary issue. The Chief Ministers of both the States have recently been advised to meet at the earliest opportunity to sort out